

Manjusha v. M.D. University and another  
(R.C. Kathuria, J.)

सूचना विवरणिका में निहित। यदि सूचना विवरणिका में निहित प्रावधान अस्थिर पाया जाता है, तो इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। विवरणिका के प्रावधान को निरस्त करने से याचिकाकर्ता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस न्यायालय को विवरणिका में निहित प्रावधान में संशोधन करना होगा या दूसरे शब्दों में इसे फिर से लिखना होगा। इस न्यायालय को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी है। उच्च न्यायालय नियम बनाने वाले प्राधिकरण की भूमिका नहीं निभा सकता है और नियम को फिर से नहीं लिख सकता है और न ही यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को उस सक्षम प्राधिकारी के स्थान पर रख सकता है जिसने विवरणिका तैयार की थी।”

(16) उपर्युक्त मामले में की गई टिप्पणियों का अनुसरण इंदु गुप्ता बनाम खेल निदेशक, पंजाब आदि के मामले में किया गया है। (2)।

(17) उपरोक्त कारणों से, हम प्रतिवादी संख्या 4 को प्रवेश देने में प्रतिवादी संख्या 2 की कार्रवाई को बरकरार रखते हैं। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रॉस्पेक्टस में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 5 को प्रवेश दिया था, इसलिए उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपने दावे के अनुसार आरक्षित श्रेणी के तहत सत्र 2000 के लिए याचिकाकर्ता in M.B.B.S पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का निर्देश दिया जाता है। इस याचिका का सहमति से निपटारा किया जाता है। इन परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आरएनआर

एन. के. सोधी और आर. सी. कथुरिया के समक्ष, जे. जे.

मंजूषा, -याचिकाकर्ता

बनाम

एम. डी. विश्वविद्यालय और एक और, -प प्रत्यर्थी

2000 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 14,632,

6दिसंबर, 2000

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-प्रवेश परीक्षा के आधार पर बी. एड. (डी. ई.) पाठ्यक्रम में प्रवेश-याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करना-पात्रता शर्तों के संदर्भ में पात्र याचिकाकर्ता-दावा करने वाला विश्वविद्यालय-इस आधार पर कि पहले से ही आयोजित प्रवेश परीक्षा-विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता के लिए एक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया।

अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता के प्रश्न की जांच ब्रोशर/प्रॉस्पेक्टस में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए, जिसमें कानून का बल है, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा रखे गए योग्यता खंड का निर्माण इससे नहीं होता है। योग्य उम्मीदवार के लिए एकमात्र आवश्यकता यह है कि उसने प्रथम और/या द्वितीय डिग्री स्तर पर कम से कम दो स्कूली विषयों का अध्ययन किया होना चाहिए और यह खंड इस बात को सीमित नहीं करता है कि इन विषयों को केवल स्कूल में ही सीखा जाना चाहिए था न कि कॉलेज में। इसलिए, कॉलेज स्तर पर दो स्कूली विषय उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को पात्र होने से बाहर करना न केवल पूरी तरह से अनुचित

### I.L.R. Punjab and Haryana

बल्कि अनुचित भी होगा। याचिकाकर्ता ने विवरणिका में निर्धारित पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा किया। प्रतिवादीगण द्वारा उसके प्रवेश पत्र की गलत अस्वीकृति के कारण उसे पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, हम इस रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और प्रतिवादीगण को निर्देश देते हैं कि वे उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए याचिकाकर्ता के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्देश दें।

(पैरा 7 और 13)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पी. के. मुतनेजा

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता विक्रान्त शर्मा

न्याय

आर. सी. कथुरिया, जे.

(1) इस याचिका में, याचिकाकर्ता ने बी. एड. (डी. ई.) पाठ्यक्रम 2000-2002 (इसके बाद 'पाठ्यक्रम' के रूप में संदर्भित) में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए उसके आवेदन पत्र की अस्वीकृति के आदेश जो उसे 11 अक्टूबर, 2000 के दिनांकित पत्र के माध्यम से सूचित किया गया (अनुलग्नक पी. 7) को रद्द करते हुए प्रमाणपत्र की एक रिट जारी करने का अनुरोध किया है। उसने आगे प्रतिवादियों के खिलाफ निर्देश की मांग की है कि उसके लिए एक नया प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाए, या उसे उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाए।

(2) याचिकाकर्ता ने मार्च, 1988 और मार्च 1990 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक और 10+2 परीक्षाओं में क्रमशः 71 प्रतिशत और 57 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। उसके बाद, उसने अप्रैल 1993, अप्रैल 1995 और दिसंबर 1999 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, प्रतिवादी संख्या 1 (जिसे आगे 'विश्वविद्यालय' कहा जाएगा) से बीकॉम, दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा इन मानव संसाधन प्रबंधन और एम.ए. (अंग्रेजी) (दूरस्थ शिक्षा) की परीक्षाएं पास कीं और क्रमशः 47%, 63% और 43% अंक प्राप्त किए। उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए, जिसके लिए 22 अक्टूबर, 2000 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, उसने 29 सितंबर, 2000 को अपना आवेदन पत्र जमा किया जिसमें उसने बताया था कि उसने 10+2 स्तर पर वाणिज्य और लेखांकन लिया था। उस परीक्षा में उसने 47% अंक प्राप्त किए थे और इस प्रकार वह प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के लिए योग्य थी। उसे आश्चर्य हुआ जब उसे 11 अक्टूबर, 2000 को दिनांकित पत्र (अनुलग्नक P-7) विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से मिला, जिसमें सूचित किया गया था कि उसका आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि उसने कम प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। तत्पश्चात्, 17 अक्टूबर, 2000 को उसने अपने प्रतिनिधि को विश्वविद्यालय से यह जानने के लिए भेजा कि जब प्रवेश पत्रिका में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम (दूरस्थ शिक्षा 2000-2002 जो कि विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है और जिसे आगे 'ब्रोशर' कहा जाएगा) में उसने सभी शर्तें पूरी की थीं, तो उसके अंक कैसे कम हो सकते हैं। 18 अक्टूबर, 2000 को उसके प्रतिनिधि को सूचित किया गया कि वह प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के लिए योग्य नहीं है क्योंकि 45% अंक की शर्त केवल बी.ए. पास करने वाले उम्मीदवारों पर लागू होती है, न कि बीकॉम परीक्षा पर। इन परिस्थितियों से मजबूर होकर, उसने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

(3) प्रतिवादियों को नोटिस ऑफ मोशन दिए जाने पर, उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया। याचिकाकर्ता के रुख का खंडन करते हुए, उन्होंने यह तर्क दिया है कि हालांकि याचिकाकर्ता ने अपनी बीकॉम परीक्षा 1800 में से 842 अंक (46.77%) और एम.ए. (अंग्रेजी) परीक्षा 800 में से 341 अंक (42.63%) प्राप्त करके पास की थी, लेकिन

**Manjusha v. M.D. University and another  
(R.C. Kathuria, J.)**

उसका मामला नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन द्वारा जारी मार्गदर्शिका/निर्देशों के अंतर्गत नहीं आता था क्योंकि उक्त निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि उक्त पाठ्यक्रम के प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/परास्नातक डिग्री होनी चाहिए जिसमें कम से कम 45% अंक हों (44.5% को 45% तक पूर्णांकित किया जाएगा) बशर्ते कि आवेदक ने प्रथम और/या द्वितीय डिग्री स्तर पर कम से कम दो स्कूल विषयों की पढ़ाई की हो। उक्त निर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यह शर्त उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने स्नातक और परास्नातक डिग्री में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। चूंकि याचिकाकर्ता ने बीकॉम परीक्षा में कुल 46.77% अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उसका मामला स्नातक/परास्नातक डिग्री स्तर पर 45% अंकों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता था, कारण यह था कि उसने अपनी बीकॉम परीक्षा में कम से कम दो स्कूल विषयों की पढ़ाई नहीं की थी। इन आधारों पर, उसके आवेदन-पत्र को अस्वीकार करना उचित था।

(4) हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी दलीलों पर विचार किया है।

(5) इस रिट याचिका में जो एकमात्र सवाल उठा है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए विवरणिका में निर्धारित मानदंड को पूरा करता है। इसलिए यह एक पूर्व-आवश्यकता है कि विवरणिका में निहित आवश्यक प्रावधान पर ध्यान दें और उसे नीचे दिया गया है:

“अध्याय-V

योग्यता की शर्तें

बी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता शर्तें इस प्रकार होंगी:

1. योग्यताएँ: एक उम्मीदवार जिसके पास निम्नलिखित योग्यता है, वह पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए पात्र होगा।

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री (44.5% को 45 प्रतिशत तक पूरा किया जाएगा) "बशर्ते कि आवेदक ने पहले और/या दूसरे डिग्री स्तर पर कम से कम दो स्कूली विषयों की पेशकश की हो"। यह शर्त स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री में 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक अंक रखने वाले उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी।

एससी/एसटी उम्मीदवारों के मामले में योग्यता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों की आवश्यकता होती है।

2. अध्यापन का अनुभव:

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम दो साल के शिक्षण अनुभव के साथ विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर मान्यता प्राप्त स्कूलों (प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर) में सेवारत नियमित शिक्षक ही पात्र होंगे। सी.बी.एस.ई द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के मामले में स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/उप-मंडल शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी/डेस्क अधिकारी द्वारा काउंटर हस्ताक्षरित निर्धारित प्रोफार्मा (परिशिष्ट-ए) पर शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र (ओं) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कोई अलग शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक विद्यालयों में सेवा की है

## I.L.R. Punjab and Haryana

तो उसे संलग्न शिक्षण अनुभव प्रमाणपत्र प्रोफार्मा की फोटोकॉपी का उपयोग करना चाहिए।

XXXXXXXXXXXX.”

(6) यह साबित करने के लिए कि याचिकाकर्ता उपर्युक्त पात्रता को पूरा करती है, उसने मैट्रिकुलेशन परीक्षा की प्रतियां (अनुलग्नक P-1), सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा (अनुलग्नक P-2), बीकॉम पार्ट-I, पार्ट II और पार्ट-III परीक्षाओं के परिणाम-सह-विस्तृत अंक पत्र (अनुलग्नक P-3), एम.ए. (फाइनेल) अंग्रेजी परीक्षा के परिणाम-सह-विस्तृत अंक पत्र (अनुलग्नक P-4) और मानव संसाधन प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के परिणाम-सह-विस्तृत अंक पत्र (अनुलग्नक P-5) की प्रतियां रिकॉर्ड पर रखी हैं। प्रमाणपत्र (अनुलग्नक P-2) से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में हिंदी कोर और अंग्रेजी कोर के अतिरिक्त गणित, वाणिज्य और लेखांकन जैसे विषय लिए थे। बीकॉम पार्ट-I परीक्षा में, उसने वित्तीय लेखांकन, व्यवसाय गणित और कंप्यूटर जागरूकता और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अलावा अन्य विषय भी लिए थे। बीकॉम पार्ट-II परीक्षा में, उसने वाणिज्यिक कानून, कंपनी कानून, मनी एंड बैंकिंग, व्यवसाय सांख्यिकी और उच्च लेखांकन जैसे विषय लिए थे। बीकॉम पार्ट-III परीक्षाओं में, याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए विषय लागत और प्रबंधन लेखांकन, व्यवसाय कराधान कानून, भारतीय आर्थिक समस्याएं और वित्तीय प्रबंधन के अलावा अन्य विषय थे।

(7) उपरोक्त डेटा के आधार पर, प्रतिवादियों की ओर से दोहरा प्रस्ताव दिया गया है ताकि उक्त पाठ्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन-पत्र को अस्वीकार करने के उनके रुख का समर्थन किया जा सके। पहला यह कि याचिकाकर्ता ने अपनी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा हिन्दू गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत से पास की थी, जो कि प्रमाणपत्र (अनुलग्नक P-2) से स्पष्ट है जो कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया था और इस कारण से यह नहीं कहा जा सकता कि उसने गणित, वाणिज्य और लेखांकन को स्कूल विषयों के रूप में पास किया था। दूसरा यह कि बीकॉम पार्ट-I और पार्ट-II परीक्षाओं के परिणाम-सह-विस्तार अंक पत्रों से यह और भी स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने गणित, वाणिज्य और लेखांकन में से दो विषयों का चयन नहीं किया था, और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि उसने प्रथम या दूसरे वर्ष की डिग्री स्तर पर कम से कम दो स्कूल विषयों की पढ़ाई नहीं की है। हमारे विचार में, यह प्रस्तुति सीधे अस्वीकार की जानी चाहिए। निस्संदेह किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता का प्रश्न ब्रोशर/प्रोस्पेक्टस में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जांचा जाना चाहिए, जिसमें कानून की शक्ति होती है, लेकिन प्रतिवादियों के प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा योग्यता खंड का जो निर्माण किया गया है, वह इससे प्रवाहित नहीं होता है। योग्य उम्मीदवार के लिए एकमात्र आवश्यकता यह है कि उसने प्रथम और/या द्वितीय डिग्री स्तर पर कम से कम दो स्कूल विषयों की पढ़ाई की हो और इस खंड में यह सीमा नहीं है कि ये विषय केवल स्कूल में ही पढ़ाए जाएं और कॉलेज में नहीं। बहस के दौरान, प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील द्वारा यह विवादित नहीं किया गया कि कुछ स्कूलों में, 10+2 स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है क्योंकि आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के कारण और मान्यता की कमी या अन्य स्कूलों में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुपलब्धता के कारण, 10+2 स्तर तक की शिक्षा कॉलेजों में प्रदान की जाती है। इस प्रकार 'स्कूल विषयों' को ब्रोशर में परिभाषित या समझाया नहीं गया है। चेम्बर्स इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, 'स्कूल' शब्द का अर्थ होता है शिक्षा के लिए स्थान; शिक्षा के लिए संस्थान, विशेषकर प्राथमिक या माध्यमिक, या विशेष विषयों की शिक्षा के लिए; ऐसे संस्थान का एक विभाग। प्रतिवादी 'स्कूल विषयों' के शब्दों की ऐसी व्याख्या नहीं कर सकते जिससे योग्य उम्मीदवारों को प्रवेश से वंचित किया जाए।

Manjusha v. M.D. University and another  
(R.C. Kathuria, J.)

वास्तविक रूप से, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा कि मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थीं, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए प्रमाणपत्रों की प्रतियों अनलग्नक P-1 और P-2 से स्पष्ट है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सीनियर सेकेंडरी परीक्षा स्कूल विषयों के प्रांत में आती है और इसी कारण से प्राधिकरणों ने परीक्षा आयोजित करने का कार्य हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड को सौंपा था। इसलिए, पात्रता खंड से उन छात्रों को बाहर करना जिन्होंने कॉलेज स्तर पर दो स्कूल विषय पास किए हैं, न केवल पूरी तरह से अनुचित होगा बल्कि मामले की परिस्थितियों के तहत अनुचित भी होगा।

(8) प्रतिवादियों की ओर से लिए गए अन्य रुख पर आते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में गणित, वाणिज्य और लेखांकन के विषय लिए थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बीकॉम पार्ट-I परीक्षा में उसने वित्तीय लेखांकन, व्यवसाय गणित, कंप्यूटर जागरूकता और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अलावा अन्य विषय भी लिए थे। इसलिए, गणित और लेखांकन के विषय बीकॉम पार्ट-I परीक्षा में शामिल हैं। यहां तक कि बीकॉम पार्ट-II परीक्षा में भी याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक कानून, कंपनी कानून, मनी एंड बैंकिंग, व्यवसाय सांख्यिकी और उच्च लेखांकन के विषय पढ़े थे, जो वाणिज्य के विषयों के घटक हैं। उच्चतर शिक्षा के स्तर पर, वाणिज्य के इन घटकों को विशेषीकृत और उन्नत शिक्षा प्रदान करने के लिए विभाजित किया गया है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता ने बीकॉम पार्ट-I और पार्ट-II में वाणिज्य और लेखांकन के विषय नहीं पढ़े थे। इस प्रकार, उसने ब्रोशर में निर्धारित पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा किया।

(9) इस तथ्य के बावजूद कि यह रिकॉर्ड पर स्थापित है कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित किया गया था, उसे प्रवेश का लाभ न देने के लिए एक प्रयास किया गया था यह कहकर कि विश्वविद्यालय पहले ही प्रवेश परीक्षा आयोजित कर चुका है और चूंकि याचिकाकर्ता परीक्षा के बाद अदालत में आई है, इसलिए वह याचिका में दावा की गई राहत की हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने, प्रतिवादियों के कहे गए रुख का खंडन करते हुए, अदालत से यह आग्रह किया कि वह याचिकाकर्ता की सहायता के लिए आए क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा उसके प्रवेश-पत्र को अस्वीकार करने की कार्रवाई न केवल ब्रोशर के प्रावधानों के खिलाफ थी, बल्कि मनमानी भी थी। उन्होंने प्रदीप सतीजा और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय<sup>1</sup>, सी. तुलसी प्रिया बनाम ए.पी. स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन और अन्य<sup>2</sup> और एम. श्रीदेवी बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, ए.पी. और अन्य<sup>3</sup> पर भरोसा जताया है।

(10) प्रदीप सतीजा के मामले (ऊपर) में, याचिकाकर्ताओं को प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि आवेदन पत्र के लिए अंतिम तिथि जिसके अनुसार याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन भेजे थे, कहा जाता था कि उन्हें गलत तरीके से समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। एक शुद्धिपत्र भी जारी किया गया था, लेकिन आवेदन पत्र जमा करने की वास्तविक अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद यह समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि याचिकाकर्ताओं को विश्वविद्यालय की लापरवाही के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए और एक निर्देश जारी किया गया था कि उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।

<sup>1</sup> ए. आई. आर. 1984 एन. ओ. सी. 19 (हिमा. प्रा.)

<sup>2</sup> जे टी 1998 (5) एस सी 246

<sup>3</sup> जे. टी 2000 (8) एस. सी. 314

## I.L.R. Punjab and Haryana

(11) सी. तुलसी प्रिया के मामले (उपरोक्त) में, अपीलकर्ता ने इंजीनियरिंग, कृषि और मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (ईएएमसीईटी) के लिए उपस्थित हुई थी। उसे एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र दिया गया था। लगभग 20 मिनट के बाद, परीक्षक ने पता लगाया कि गलत पेपर दिया गया था और इस कारण से पेपर बदल दिया गया। कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया गया और इस प्रकार, उम्मीदवार के पास केवल 2-1/2 घंटे पेपर का उत्तर देने के लिए थे। उसने 200 में से 170 प्रश्नों का उत्तर दिया और 94.55% अंक प्राप्त किए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह निर्देश दिया गया कि अपीलकर्ता को 94.55% अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए विचार किया जाए।

(12) एम.श्रीदेवी के मामले (सुप्रा) में, योग्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं माना गया था। उच्च न्यायालय की एक विभाजन पीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया और देखा कि, स्वीकार्य रूप से, यदि इस सिद्धांत का पालन किया गया होता, तो अपीलकर्ता को पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल जाता और उसने यूनिवर्सिटी के आचरण के कारण पीड़ा झेली है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांत का पालन नहीं किया था, लेकिन आवश्यक परिणामी राहत प्रदान नहीं की गई थी। जब अपील सर्वोच्च न्यायालय में ले जाई गई, तो उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया गया और निर्णय के पैरा 3 में इस प्रकार टिप्पणी की गई थी:

“3. अगर यह विश्वविद्यालय की गलती थी, जैसा कि विभाजन पीठ ने पाया, तो यह उचित था कि विश्वविद्यालय को उचित सुधार करने के निर्देश दिए जाएं। हमारा ध्यान इस न्यायालय के निर्णय और आदेश की ओर आकर्षित किया गया है C. तुलसी प्रिया बनाम ए.पी. राज्य परिषद उच्च शिक्षा और अन्य (JT 1998 (5) SC 246 = 1998 (6) SCC 284) में भी जहां विश्वविद्यालय ने छात्र के नुकसान के लिए एक गलती की थी और इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि छात्र को उस राज्य के कोटे से उस अकादमिक वर्ष में सही और गलत आधार पर नहीं; राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए विचार किया जाना चाहिए।”

(13) उपर्युक्त उल्लेखित मामलों में निर्धारित कानूनी सिद्धांत के अनुसरण में, याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा उसके प्रवेश-पत्र की गलत अस्वीकृति के कारण पीड़ित नहीं होने दिया जा सकता। इसलिए हम इस रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के लिए उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं। यदि वह परीक्षा पास करती है और योग्यता में स्थान प्राप्त करती है, तो उसे प्रवेश दिया जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आयुष  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार  
हिसार, हरियाणा

Manjusha v. M.D. University and another  
(R.C. Kathuria, J.)